

अद्यतन भूमि अभिलेख

प्रलिस के लयः

वन अधकलर अधनलयम 2006, डकलडल भूमलअभललख, सरकलर कल पहल

मेन्स के लयः

वन अधकलर अधनलयम कल वशलषतलएँ, डकलडल भूमलअभललख, भूगूकलक सूकनल प्रणलली, संबंधतल पहल

करकल में क्यूँ?

हलल ही में केंद्र सरकलर ने देश के सभल रलक्यूँ कू तीन महीने के भीतर **रलकस्व और वन अभललखूँ में बंदूबस्त अधकलर दरूक** करने कल नरलदेश दलय है ।

- पत्र में कलल गलय है कल रलकस्व और वन वभलगूँ कू **वन अधकलर अधनलयम (FRA), 2006** के तहत समूदलयूँ कू दी गई वन भूमलकल अंतमल नकशल तैयलर करनल कलहलय ।

अधसूकनल के मुख्य बदलः

परकलयः

- अनुसूकतल जनकलतल और अनूय पारंपरकल वन नवलसल (वन अधकलरूँ कल मलनूयतल) अधनलयम, 2006 यल वन अधकलर अधनलयम (FRA) के तहत अधकलरूँ के रकूँरूड पर डकलडल जनकलरल (RoR) कू (एक कलनूनी दसतलवेक जो भूमल और उसके मलकलक के बलरे में ववलरण देतल है) परवलश (PARIVESH) पूर्टल और केंद्रीय तथल रलक्य सरकलर के वभलगूँ के अनूय वेब **भूगूकलक सूकनल प्रणलली (GIS)** प्लेटफारूँ में एकूकृत कलय कलएणल ।
 - यह अधकलरूँ के नपलतलन और मलकलकलनल हक कलरल करने कल प्रकूरलय पूरल होने के बलद कलय कलएणल । मलनकतलर कू संबंधतल रलक्य कलनूनी के तहत भूमलअभललखूँ में शलमलल कलय कलनल कलहलय ।
- मंतूरललय ने रलक्यूँ कू प्रतूयक भूमल पैक कल भूगूकलक सूकनल प्रणलली (GIS) सरूवेकूषण करने और बहुभुजूँ कल भू-संदरूभतल डकलडल वेकूटर सीमलओँ कू बनलए रखने कल भी नरलदेश दलय है ।

ललभः

- FRA के डेटल के अनुसलर भूमल रकूँरूड आदवलसलयूँ और अधकलरलयूँ के बीच संघरूष कू समलपूत करतल है ।
 - कभी-कभी FRA के तहत आवंततल भूमलकल टुकूडल वनीकरण के ललय उपयूकल कलय कलतल है कलससे दूनों पकूषूँ के ललय बहुत सलरल समसूयलएँ उत्पन्न हूतल है ।
- FRA के तहत RoR कल भू-संदरूभ रलक्यूँ के लूगूँ के ललय फलयदेमंद हूगल क्यूँकवलन और आदवलसल कललयण वभलग FRA शीरूषक धलरकूँ कल आकूवलकल में सुधलर के ललय वशलषलट परलयकनलओँ और यूकनलओँ कू शूरू करने में सकूषम हूँगे ।

वन अधकलर अधनलयम, 2006ः

- यह अधनलयम पीढ़लयूँ से वन में नवलस करने वलली अनुसूकतल जनकलतलयूँ (FDST) और अनूय पारंपरकल वनवलसलयूँ (OTFD) कू वन भूमल पर उनूके वन अधकलरूँ कू मलनूयतल देतल है ।
- कसलल भी ऐसे सदसूय यल समूदलय दवलरल वन अधकलरूँ कल दलवल कलय कल सकतल है, जो दसलंबर 2005 के 13वें दनल से पहले कम-से-कम तीन पीढ़लयूँ अथवल 75 वरूष से वन भूमल में वलसूतवकल आकूवलकल कल जरूरतूँ हेतू नवलस करतल है ।
- यह FDST और OTFD कल आकूवलकल तथल खलदूय सुरकूषल सुनशलकतल करते हूए वनूँ के संरकूषण कल वूयवसूथल कू मकूबूतल प्रदलन करतल है ।
- गुरलम सभल** कू वूकूतगत वन अधकलर (IFR) यल सलमूदलयकल वन अधकलर (CFR) यल दूनों कू कल FDST और OTFD कू दलय कल सकते हैं, कल प्रकूतलएवं सीमल नरलधलरतल करने हेतू प्रकूरलय शूरू करने कल अधकलर है ।
- इस अधनलयम के तहत कलर प्रकूरलर के अधकलर हैंः**
 - सवलमतलतूव अधकलरः** यह FDST और OTFD कू अधकलतम 4 हेकूटेयर भू-कूषेतर पर आदवलसलयूँ यल वनवलसलयूँ दवलरल खेती कल कलने

वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिये है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है, इसके अलावा कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी।

- **उपयोग करने का अधिकार:** वन नविसायियों के अधिकारों का वसितार **लघु वनोत्पाद**, चराई क्षेत्रों आदितिक है।
- **राहत और विकास से संबंधित अधिकार:** वन संरक्षण के लिये प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली या जबरन वसिस्थापन और बुनयिादी सुवधियाओं के मामले में पुनरवास का अधिकार शामिल है।
- **वन प्रबंधन अधिकार:** इसमें कसिी भी सामुदायिक वन संसाधन की रकषा, पुनः उत्थान या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है, जसिे वन नविसायियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से संरक्षणित एवं सुरक्षणित कयिा जाता है।

डजिटल भूमि रिकॉर्ड हेतु भारत की पहलें:

- **स्वामित्व (SVAMITVA):**
 - स्वामित्व डुरोन तकनीक और कंटीनयूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन (CORS) का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि मानचित्रण की एक योजना है।
 - वर्ष 2020 से 2024 तक चार वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से देश भर में मानचित्रण कयिा जाएगा।
- **परविश (PARIVESH) पोर्टल:**
 - **परविश** एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जसिे केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय वनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zones- CRZ) की मंजूरी प्राप्त करने के लिये प्रस्तावकों द्वारा दयिे गए प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुता और नगिरानी हेतु वकिसति कयिा गया है।
- **भूमि संवाद:**
 - **भूमि संवाद** डजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Workshop on Digital India Land Record Modernisation Programme- DILRMP) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला है।
 - यह देश भर में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (Integrated Land Information Management System- ILIMS) वकिसति करने के लिये वभिन्न राज्यों में भूमि अभलिखों के क्षेत्र में मौजूद समानताओं को स्थापति करने का प्रयास करता है, जसिे पर वभिन्न राज्य राज्य-वशिषिट आवश्यकताओं को भी जोड़ सकते हैं जैसा कि वे प्रासंगिक और उपयुक्त समझ सकते हैं।
- **राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली:**
 - यह मौजूदा मैनुअल पंजीकरण प्रणाली से बकिरी-खरिद और भूमि के हस्तांतरण में सभी लेन-देन के ऑनलाइन पंजीकरण की ओर एक बड़ा बदलाव है।
 - यह राष्ट्रीय एकता की दशिा में एक बड़ा कदम है और 'वन नेशन वन सॉफ्टवेयर' को भी बढ़ावा देगा।
- **वशिषिट भूखंड पहचान संख्या**
 - ULPIN को 'भूमि की आधार संख्या' के रूप में वर्णित कयिा जाता है। यह एक ऐसी संख्या है जो भूमि के उस प्रत्येक खंड की पहचान करेगी जसिका सरवेक्षण हो चुका है, वशिष रूप से ग्रामीण भारत में, जहाँ सामान्यतः भूमि-अभलिख काफी पुराने एवं वविदति होते हैं। इससे भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS):

- वेब आधारित भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) में वेब तथा अन्य परसिंचालनों का उपयोग करस्थानिक जानकारी का अनुप्रयोग, सूचनाओं को संसाधित एवं प्रसारित कयिा जाता है।
- यह उपयोगकर्ताओं के आँकड़ों के एकत्रीकरण, वशि्लेषण एवं परिणामों को अधिक-से-अधिक व्यक्तियों तक प्रसारित करने में मदद करता है तथा नीति निर्माताओं के लिये उपयुक्त आँकड़ों को उपलब्ध कराने में मदद करता है।
 - GIS ऐसी कसिी भी जानकारी का उपयोग कर सकता है जसिमें स्थान शामिल है। स्थान को कई अलग-अलग तरीकों से व्यक्त कयिा जा सकता है, जैसे- अक्षांश और देशांतर, पता या ज़पि कोड।
- GIS में लोगों से संबंधित आँकड़े जैसे- जनसंख्या, आय या शकिषा का स्तर आदि डेटा शामिल हो सकता है।
 - इसमें कारखानों, खेतों, स्कूलों, तूफानों, सड़कों और वदियुत लाइनों आदि के संबंध में जानकारी भी शामिल हो सकती है।

UPSC सविलि सेवा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन नविसी (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियिम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

- (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (b) पंचायती राज मंत्रालय
- (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (d) जनजातीय मामलों का मंत्रालय

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के रूप में भी जाना जाता है, वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है।
- अधिनियम में खेती और निवास जो आमतौर पर व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में होते हैं और सामुदायिक अधिकार जैसे चराई, मछली पकड़ना एवं जंगलों में जल नकियाँ तक पहुँच, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs) के लिये आवास अधिकार आदि अधिकार शामिल हैं।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और नपिटान अधिनियम, 2013 में उचित मुआवज़े एवं पारदर्शिता के अधिकार के संयोजन के साथ FRA आदिवासी आबादी को पुनर्वास तथा उनके लिये उचित बंदोबस्त के बनिा बेदखली से रक्षा करता है।
- **जनजातीय मामलों के मंत्रालय** के तहत अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नयियों के अनुसार विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं को लागू किया जाता है।

अतः विकल्प (d) सही है।

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में समाविष्ट है।
2. भारत में पहली बार बैगा (जनजाति) को पर्यावास का अधिकार दिया गया है।
3. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिये पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से नरिणय लेता है तथा इसकी घोषणा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

व्याख्या:

- "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" को वन अधिकार अधिनियम, 2006 में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिन्हें वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा नरिधारित एवं अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। **अतः कथन 1 सही है।**
- बैगा समुदाय (मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में) भारत में 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक है, जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत पर्यावास अधिकार प्राप्त करने के पात्र हैं। वर्षों से वनों पर राज्य के बढ़ते नरिंतरण और वन भूमि स्वरूप में परिवर्तन, विकास एवं संरक्षण से इन वन समुदायों को गंभीर रूप से खतरा है। अतः वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा जनजाति के पर्यावास अधिकारों को मान्यता प्रदान की, यह जनजाति भारत में पर्यावास का अधिकार प्राप्त करने वाला पहला समुदाय बन गया है। **अतः कथन 2 सही है।**
- PVTGs के पर्यावास अधिकारों को राज्यों में ज़िला स्तरीय समिति द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय PVTGs के संदर्भ में आवास अधिकारों की परिभाषा के दायरे और सीमा को स्पष्ट करता है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

अतः विकल्प A सही है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ